Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 2, October-2020, ISSN 2230-7540

अनुसूचित जनजातियों की घरेलू आय और व्यय का अध्ययन

Shadhna Yadav[1]*, Dr. Umesh Kumar Yadav[2]

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

[2] Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

सार - अनुसूचित जातियाँ सदियों से सामाजिकयोंआर्थिक शोषण की शिकार रही हैं और उन्हें निम्न व्यवसा-, कम आय वाले व्यवसायों, अस्वच्छ वातावरण और दूषित शौकिया व्यवसायों में भेज दिया गया है। यद्यपि देश के कई हिस्सों में अस्पृश्यता प्रथा का क्षय हो रहा है, फिर भी जाति की कठोरता कई अनुसूचित जाति के मजदूरों को अशोभनीय व्यवसायों में सीमित कर देती है जो अन्य समुदायों की तुलना में उन्हें नुकसान में डालते हैं। और जिस अध्ययन के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूचित जाति ,व्यय,अनुसूचित जाति विकास निगम, अनुसूचित जनजाति (एसटी), जनजातीय लिंग अनुपात, भारत में जनजातीय गरीबी है।

खोजशब्द - जातियों, जनजातियों

---------------------------------X--------------------------------

परिचय

'अनुसूचित जाति' का अर्थ ऐसी जातियों या जातियों या जनजातियों या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के समूहों के कुछ हिस्सों से है जिन्हें अनुच्छेद 341 के तहत 'अनुसूचित जाति/संविधान के उद्देश्य के लिए माना जाता है। भारत में सभी आधिकारिक और गैर-सरकारी अभिलेखों में 'अनुसूचित जाति' और 'हरिजन' को पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि अनुसूचित जाति अछूतों का पर्याय नहीं हो सकती है, वास्तव में, बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के साथ अछूतों के रूप में भेदभाव किया जाता है। जैसे, सभी प्रकार के भेदभाव से पीड़ित इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए, भारत का संविधान विकास की प्रक्रिया में बाकी भारतीयों के साथ पकड़ने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रियायतें प्रदान करता है। इस संबंध में कुछ मामलों को उनके द्वारा झेली गई सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं के आधार पर अनुसूची में शामिल किया गया है। इन लोगों को 'अनुसूचित जाति' के रूप में जाना जाता है।[1]

अनुसूचित जातियाँ सदियों से सामाजिक-आर्थिक शोषण की शिकार रही हैं और उन्हें निम्न व्यवसायों, कम आय वाले व्यवसायों, अस्वच्छ वातावरण और दूषित शौकिया व्यवसायों में भेज दिया गया है। यद्यपि देश के कई हिस्सों में अस्पृश्यता प्रथा का क्षय हो रहा है, फिर भी जाति की कठोरता कई अनुसूचित जाति के मजदूरों को अशोभनीय व्यवसायों में सीमित कर देती है जो अन्य समुदायों की तुलना में उन्हें नुकसान में डालते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज में एक कठोर, व्यवसाय-आधारित, पदानुक्रमित जाति व्यवस्था थी जिसमें सामाजिक पदानुक्रम में किसी जाति का सापेक्ष स्थान उसके पारंपरिक व्यवसाय द्वारा निर्धारित किया जाता था। आज भी, बहुसंख्यक अनुसूचित जातियों के साथ हर तरह से भेदभाव किया जाता है और उन्हें पूंजी जैसी उत्पादक संपत्ति के स्वामित्व से वंचित किया जाता है, साथ ही शिक्षा और समानता जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका अत्यधिक सामाजिक-आर्थिक अभाव बना रहता है।

भारतीय सामाजिक संरचना का नेतृत्व हिंदू जाति व्यवस्था द्वारा किया जाता है। जाति का तात्पर्य सामाजिक असमानता की एक कठोर प्रणाली से है जिसमें गतिशीलता के लिए प्रमुख बाधाएं या विविध स्तरों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। "जाति" शब्द की

उत्पत्ति स्पैनिश शब्द "कास्टा" से हुई है, जिसका अर्थ है "नस्ल, नस्ल, नस्ल या विरासत में मिले गुणों का एक समूह"। पुर्तगालियों ने इस शब्द को भारत में लोगों के वर्गों से जोड़ा, जिन्हें 'जाति' के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी शब्द 'जाति' मूल शब्द 'कास्ट' का समायोजन है। वर्ग के आधार पर विभाजन एक सार्वभौमिक घटना है, लेकिन हिंदू जाति व्यवस्था की विशेषता यह है कि यह जन्म पर आधारित है न कि योग्यता पर। चार जातियों की बड़ी छतरी के नीचे ब्राहमण (पुजारी), क्षत्रिय (रईस, सैनिक), वैश्य (कारीगर, व्यापारी) और शूद्र (श्रमिक बल), सैकड़ों और सैकड़ों उपजातियाँ हैं।[2]

शुद्धता और प्रदूषण की धारणा पर आधारित भारतीय जाति व्यवस्था का मानना था कि अनुसूचित जातियां अशुद्ध और प्रदूषित हैं। उन्हें मुख्यधारा के समाज से बाहर रखा गया और मंदिरों के भीतर रोक दिया गया, उच्च जाति के कुओं से पानी लाने और उच्च जाति के हिंदुओं के साथ सभी सामाजिक संचार। जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण, अनुसूचित जातियों को बहिष्कृत, सीमांत, दलित, प्रदूषित माना जाता है और सदियों से उच्च जातियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है।

सदियों से, अनुसूचित जातियों में विभिन्न जाति समूह शामिल हैं, जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से पीड़ित हैं। वे सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे रहते हैं और प्राचीन काल से उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से उदास, विभेदित और शोषित हैं। 19वीं शताब्दी में, ज्योतिबा फुले ने 'दलित' शब्द का इस्तेमाल उन्हें जातिग्रस्त समाज के सबसे उत्पीड़ित और टूटे हुए पीड़ितों के रूप में वर्णित करने के लिए किया था। इन अछूतों या अनुसूचित जातियों को आधिकारिक तौर पर 1932 में दलित जातियों के रूप में परिभाषित किया गया था और उन्हें व्यवस्थित रूप से भारत की जनगणना (1931) में सूचीबद्ध किया गया था। अछूतों को 'हरिजन' नाम महात्मा गांधी ने दिया था। 'हरि' का अर्थ है 'भगवान' और 'जन' का अर्थ है 'लोग', यानी, 'भगवान के लोग', विभिन्न भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी और अन्य में इस शब्द का अर्थ 'एक बच्चा है जिसके पिता की पहचान रहस्यमय है'। इसलिए, इन जातियों द्वारा 'हरिजन' नाम का विरोध और नफरत की गई थी।[3]

भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है; और, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लोगों के मामले में पहला सबसे बड़ा देश। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) दुनिया के कई देशों की तुलना में तेज दर से बढ़ रहा है। लेकिन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने, सोने और सड़कों के किनारे शौच करने और भीख मांगने की आबादी भी बढ़ती जा रही है। भारत में विश्व स्तरीय धनवानों की संख्या बढ़ रही है; लेकिन गरीबी का स्तर कम नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी के बीच गरीबी का स्तर और गरीबी की घटनाएं अधिक हैं।[4]

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आधिकारिक तौर पर लोगों के नामित समूह हैं और भारत में सबसे वंचित सामाजिक-आर्थिक समूहों में से हैं। शर्तों को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है और समूहों को एक या अन्य श्रेणियों में नामित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की अधिकांश अवधि के लिए, उन्हें दलित वर्गों के रूप में जाना जाता था।[5]

आधुनिक साहित्य में, अनुसूचित जातियों को कभी-कभी दलित के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है "एकजुट / एक साथ समूहित", जिसे बी.आर. अम्बेडकर (1891-1956), एक दलित स्वयं, एक अर्थशास्त्री, सुधारक, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। , और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दलित नेता। अम्बेडकर ने गांधी के शब्द हरिजन के स्थान पर दलित शब्द को प्राथमिकता दी, जिसका अर्थ है "हरि/विष्णु का व्यक्ति" (या भगवान का आदमी)। सितंबर 2018 में, सरकार ने "सभी निजी उपग्रह चैनलों को एक एडवाइजरी जारी कर उन्हें 'दलित' नाम का उपयोग करने से 'बचाने' के लिए कहा", हालांकि "अधिकार समूह और बुद्धिजीवी लोकप्रिय उपयोग में 'दलित' से किसी भी बदलाव के खिलाफ सामने आए हैं" .

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भारत की आबादी का क्रमश: लगभग 16.6% और 8.6% शामिल है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 अपनी पहली अनुसूची में 28 राज्यों में 1,108 जातियों को सूचीबद्ध करता है, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 अपनी पहली अनुसूची में 22 राज्यों में 744 जनजातियों को सूचीबद्ध करता है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का दर्जा दिया गया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई, और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सकारात्मक भेदभाव के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है।[6]

व्यय

व्यय को फसल की खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और उपभोग में बांटा गया है। खपत को आगे भोजन और गैर-खाद्य में विभाजित किया गया है। भोजन में चावल, बाजरा, मसाले, मांस, नशीला पदार्थ और खाने के लिए तैयार भोजन शामिल हैं। गैर-खाद्य व्यय में कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन और विविध वस्तुएं शामिल हैं। वेल्लार समुदाय के लिए ये सभी व्यय मदें बड़ी हैं। चूंकि सन्नार पास के जंगल में रहते हैं, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वेल्लालर उत्तरदाताओं को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। वेल्लार उत्तरदाताओं ने निजी अस्पतालों को प्राथमिकता दी। सन्नार समुदाय के उत्तरदाता मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। वेल्लालर उत्तरदाता अधिक बार प्रवास करते हैं उपभोग करने के लिए आने से अधिकांश सन्नार शाकाहारी होते हैं जबकि सभी वेल्लालर मांसाहारी भोजन भी खाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में ऐसी कोई दुकान नहीं है जो खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ बेचती हो। उत्तरदाताओं को तैयार खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए 20 किमी से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। जब भी वे आस-पास के शहरों में जाते हैं। वे ज्यादातर तैयार खाद्य पदार्थ और सब्जियां खरीदते हैं। गांव की दुकानों में बीड़ी और सिगरेट सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं। [7]

अनुसूचित जाति विकास निगम

राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगमों को आर्थिक विकास की बैंक योग्य योजनाओं के संबंध में गरीब अनुसूचित जाति उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों के बीच इंटरफेस करने की परिकल्पना की गई है। इन निगमों का मुख्य कार्य उत्प्रेरक, प्रमोटर और गारंटर के रूप में कार्य करके अनुसूचित जाति के उद्यमियों के आर्थिक विकास के लिए संस्थागत ऋण जुटाना है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों की विशेष घटक योजना के तहत कुल आवंटन रुपये के क्रम का था। 4204.00 करोड़ और रुपये की राशि। 3553.00 करोड़ वास्तव में खर्च किए गए हैं। यह रुपये के व्यय की राशि की विशेष केंद्रीय सहायता द्वारा पूरक था। रुपये के प्रावधान के मुकाबले राज्य एससीडीसी द्वारा 595.00 करोड़ रुपये। 600.00 करोड़। इस योजना में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवारों को गरीबी रेखा पार करने का निश्चित लक्ष्य पहली बार अपनाया गया था। यह बताया गया है कि योजना अवधि के दौरान 96 लाख अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले, विभिन्न गरीबी विरोधी योजनाओं के तहत 103 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में, 19 एससीडीसी को देश में रु. की कुल पूंजी के साथ संचालित पाया गया। 173.00 करोड़। इन एससीडीसी ने एमएमएल और बैंक योग्य योजनाओं के तहत 2.7 मिलियन अनुसूचित जाति परिवारों की सहायता की। 635.00 करोड़। इस योजना अवधि के दौरान 6.88 लाख अनुसूचित जाति परिवारों के बीच 13.33 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यकरण पर, योजना आयोग ने खुलासा किया कि "एससी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्यों द्वारा तैयार एससीपी की एक उत्साहजनक विशेषता यह है कि योजनाओं की गुणवत्ता और उनके कार्यान्वयन ने पिछले पिछली योजनाएँ। हालाँकि, संगठनात्मक सुधार, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और लक्षित समूहों के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के बीच उचित जुड़ाव की दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। देखी गई कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ राज्य से ब्लॉक स्तर तक विकेंद्रीकरण की कमी से संबंधित हैं, उनके बीच पर्याप्त संचार, और जमीनी स्तर पर एक उचित रिपोर्टिंग और निगरानी मशीनरी"।[8-9]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास को लाने के लिए विशेष घटक योजना की रणनीति को और अधिक गहन तरीके से जारी रखने का सुझाव दिया। कार्य दल ने पूर्व की योजनाओं के दौरान कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुभव की गई कमियों को दूर करने और प्रशासन, कार्यान्वयन और कार्यक्रमों के उचित मूल्यांकन के संबंध में सुधार के उपाय करने की सिफारिश की। सातवीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एससीपी के तहत आवंटित कुल राशि रु. जिसमें से 7385.42 करोड़ रु, योजना अवधि के दौरान

विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए वास्तव में 6916.92 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसे रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता के साथ पूरक किया गया है। 930.00 करोड़ जिसमें से रु. योजना अवधि के दौरान वास्तव में 876.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 190 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को वजीफा और छात्रवृत्तियां दी गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम और राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों को रोजगार सृजन के लिए योजनाएं विकसित करने और इन समुदायों के आर्थिक विकास के लिए पायलट परियोजनाओं को खोजने में उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है। इस योजना अवधि के दौरान 118.82 लाख अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। 21 राज्यों के एससीडीसी के माध्यम से 22.56 लाख अनुसूचित जाति परिवारों को मार्जिन मनी ऋण वितरित किया गया है।[10]

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान, रुपये का परिव्यय। केंद्रीय योजना में 2548.00 करोड़ रुपये सहित। 1125.00 राज्यों की विशेष घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में और रु. अनुसूचित जाति के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य योजना क्षेत्र के लिए 3086.06 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। आठवीं योजना अवधि के अंत तक, कुल 24.82 लाख (96.90 प्रतिशत) अनुसूचित जाति परिवारों को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत 25.62 लाख परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले सहायता प्रदान की गई थी।

निरंतरता के रूप में, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान, इन लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और गरीबी रेखा को पार करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है। इस योजना अवधि के दौरान रु. केंद्रीय योजना के तहत 5399.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें विशेष केंद्रीय सहायता भी शामिल है। राज्य क्षेत्र के तहत 9568.68 करोड़। 1997-98 के दौरान, विभिन्न राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के माध्यम से विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत कुल 4.62 लाख अनुसूचित जातियों को सहायता प्रदान की गई है।[11]

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के कारण, देश में अनुसूचित जाति के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय विकास हुआ है। अनुसूचित जाति के परिवारों में गरीबी की घटना 1977-78 के दौरान 64.60 प्रतिशत थी जो 1987-88 में घटकर 54.70 प्रतिशत और बाद में 1993-94 में 48.37 प्रतिशत हो गई। पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरता दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर 1961 में 10.27 से बढ़कर 1991 की जनगणना में 37.41 हो गई है। महिला साक्षरता दर भी 1971 में 6.44 से बढ़कर 1991 में 23.70 हो गई है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी उपायों के कारण अनुसूचित जातियों के बीच व्यावसायिक विविधीकरण हुआ है। उनके पारंपरिक अस्वच्छ व्यवसायों से आधुनिक व्यवसायों में बदलाव आया है। कृषि गतिविधियों में लगे अनुसूचित जाति के श्रमिकों का प्रतिशत 1971 में 80.00 से घटाकर 1991 में 77.50 कर दिया गया है और इस अवधि के दौरान गैर-कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी 20 प्रतिशत से बढ़कर 22.50 प्रतिशत हो गई है। सेवाओं में आरक्षण के कारण, सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व 1974 में 13.66 प्रतिशत से बढ़कर 1994.38 में कुल पदों का 16.90 प्रतिशत हो गया है, इसके अलावा, समूह ए और बी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व जो कि 1974 में 3.25 और 4.59 प्रतिशत था। 1994 में कुल पदों का क्रमशः 10.25 और 12.06 प्रतिशत हो गया। इस्साक की पढ़ाई: 1972, पटवर्धन: 1973, सिंह: 1987, चेट्टी: 1991, जयकुमार: 1995, श्रीवास्तव और मुर्या; 2000 ने दिखाया है कि सरकार के कल्याणकारी उपायों ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार किया है। योजना आयोग ने कहा, "विभिन्न विकास योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव ने अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में एक स्पष्ट सुधार लाया है"।

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

सबसे बड़ी जनजातीय आबादी अफ्रीका में पाई जाती है। अधिकांश आदिवासी आबादी सुदूर वन और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। भारत सरकार ने 75 आदिवासी समुदायों को अधिसूचित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 10 करोड़ थी जो भारत की कुल आबादी का लगभग नौ प्रतिशत थी। इनमें से 90 फीसदी ग्रामीण इलाकों में और बाकी 10 फीसदी शहरी इलाकों में रह रहे हैं। अनुसूचित जनजाति की आधी से अधिक आबादी

मध्य भारत में केंद्रित है अर्थात् मध्य प्रदेश (14.69%), छत्तीसगढ़ (7.5%), झारखंड (8.29%), आंध्र प्रदेश (5.7%), महाराष्ट्र (10.08%), उड़ीसा (9.2%), गुजरात (8.55%) और राजस्थान (8.86%)। अन्य विशिष्ट क्षेत्र उत्तर पूर्व (असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश) हैं। सांख्यिकीय रूप से मजबूत अनुसूचित जनजाति समूहों में संथाल, गोंड, भील, उरांव शामिल हैं। छोटे आदिवासी समूह A&N द्वीप समूह (अंडमानी, ओन्गेस), केरल और तमिलनाडु (पानियन और कट्टुनाइकेंस) में पाए जाते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, 1911, ने एक जनजाति को "एक सामान्य नाम रखने वाले परिवारों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया है, एक सामान्य बोली बोल रहा है, एक सामान्य क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है या कब्जा कर रहा है और आमतौर पर अंतर्विवाही नहीं है, हालांकि मूल रूप से ऐसा हो सकता है".

जनजातीय लिंग अनुपात

एसटी के संबंध में लिंग अनुपात 990 है जो राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। साथ ही, एसटी लिंग अनुपात 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 हो गया है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आदि। , ने उच्च एसटी लिंग अनुपात दिखाया है जबकि जम्मू और कश्मीर ने 2011 में सबसे कम एसटी लिंग अनुपात 924 दिखाया है।[12-13]

भारत में जनजातीय गरीबी

भारत में योजना आयोग ने तेंदुलकर पद्धति के आधार पर गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया है। इन अनुमानों के अनुसार, 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और शहरी क्षेत्रों में 24 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति बीपीएल रहते थे। गैर-अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए ये अनुमान क्रमशः 26 प्रतिशत और 14 प्रतिशत थे।

निष्कर्ष

अध्ययन का उद्देश्य यह देखना था कि क्या गरीब और गैर-गरीब परिवारों के बीच कोई अंतर है। अधिक विशेष रूप से शोध प्रश्न यह देखने के लिए था कि क्या गरीब परिवारों की तुलना में गैर-गरीब परिवारों की जीवन शैली और जीवन स्तर बेहतर है या नहीं। इस उद्देश्य के लिए जवाधु पहाड़ियों में एक अनुभवजन्य संदर्भ चुना गया था, क्योंकि आदिवासी आबादी में गरीबी गंभीर है। चुना गया राजस्व गांव पुलियूर था। अध्ययन गांव में कुछ बस्तियां हैं। सभी घरों से कुल 113 घर बनाए गए थे। इन परिवारों को बीपीएल और एपीएल में रहने वाले परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बीपीएलएच की संख्या 76 थी और एपीएलएच 37 थी। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गांवों में गरीब और गैर-गरीब परिवारों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। गैर-गरीब परिवारों की अपेक्षाकृत बड़ी जोत, आय और व्यय का उनके जीवन स्तर में सुधार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। गांवों में परिवार उनकी आय और जोत के आकार के बावजूद लगभग समान हैं। इसलिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. अनुपमा नल्लारी (2015): "हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर शौचालय हों", पर्यावरण और शहरीकरण, वॉल्यूम। 27, नंबर 1, पीपी। 73-88।
2. आशा शशिधरन (2017): "आजीविका संक्रमण: जनजातीय जीवन पर सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव", जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, वॉल्यूम। 2 (3), आईएसएसएन: 2456-2068, पीपी। 09-17. भारत की जनगणना (2011): "भारत सरकार"।
3. चंदेल, यादव, और झरिया (2017): "सरगुजा डिवीजन के आर्थिक और पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद", पर्यावरण, फार्माकोलॉजी और जीवन विज्ञान के बुलेटिन, खंड 6 (5), पीपी। 32-39.
4. प्रसन्ना और कुरिंजमलार (2017): "ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन पर MGNREGP का प्रभाव तमिलनाडु में दो जिलों का एक केस स्टडी", जर्नल ऑफ एकेडेमिया एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (JAIR), खंड 5, अंक 9, पीपी। 139-142.
5. राजशेखर, मंजुला, सुचित्रा (2017): "माइक्रोफाइनेंस आजीविका को बढ़ावा देता है और आदिवासियों के बीच कमजोरियों को कम करता है: कर्नाटक और तमिलनाडु से कुछ गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप का एक

www.ignited.in

अध्ययन", सामाजिक परिवर्तन, वॉल्यूम। 47 (1), सेज प्रकाशन, पीपी। 65-80।

6. सिंह, एस., और ठाकुर, डी.एस. (2005)। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच पूर्ण गरीबी की सीमा: एक पोषण प्लस दृष्टिकोण। रिसर्च जर्नल सोशल साइंसेज, 13 (3), 26-43।
7. सिन्हा, बी. (2005). भारत के चयनित राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच शिक्षा में लैंगिक असमानता। द इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, 53 (3), 131-144
8. श्रीनिवासन, के., और मोहंती, एस.के. (2004)। जाति और धर्म द्वारा बुनियादी सुविधाओं से वंचित: एनएफएचएस डेटा का उपयोग कर अनुभवजन्य अध्ययन। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 39 (7), 728-735।
9. स्वामीनाथन, एम., और रावल, वी. (2011)। ग्रामीण भारत में आय असमानता: जाति की भूमिका। ECINEQ, आर्थिक असमानता के अध्ययन के लिए सोसायटी, वर्किंग पेपर सीरीज़, 2-17।
10. थोराट, एस., और ली, जे. (2005)। जाति भेदभाव और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, एक्स्ट्रा लार्ज (39), सितंबर, 4198-4201।
11. थोराट, एस., और सभवाल, एन.एस. (2006)। अनुसूचित जातियों के ग्रामीण गैर-रोजगार: एक तुलनात्मक अध्ययन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, वर्किंग पेपर सीरीज, 1 (5), 1-15।
12. थोराट, एस (2007)। आर्थिक बहिष्करण और गरीबी: बहिष्करण के खिलाफ उपचार का भारतीय अनुभव। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और एशियाई विकास बैंक, एडीबी मुख्यालय, मनीला, फिलीपींस, 1-17।
13. थोराट, एस। (2010)। सामाजिक बहिष्करण और मानव गरीबी: समावेशी नीति के माध्यम से सुरक्षा। द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 53 (1), 23-39।

Corresponding Author

Shadhna Yadav*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.